

Shri Jashvant Mehta: Mr. Kaldor had given some figures in respect of tax evasion, and after that, so many years have passed. May I know what is the assessment of the Government, at present, in respect of the amount of tax evasion in this country?

Shri B. R. Bhagat: We cannot give the estimates. It is very difficult to give them. Prof. Kaldor or some hon. Member can give the estimate, but it is very difficult for us, as Government, to give it.

Shri A. N. Vidyalankar: May I know whether the Government have been publishing the names of the tax evaders from time to time?

Shri B. R. Bhagat: It has been provided in law that in certain cases the names may be given.

Shri A. N. Vidyalankar: I want to know whether that is done.

Mr. Speaker: Order, order.

श्री तुलशीदास जाधव : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि जो लोग एक फर्म से इवेजन करते हैं वही दूसरी फर्म निकालते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : सरकार को यह मालूम है और भी बहुत सी बातें मालूम हैं ।

Squatters in Delhi

- *336. { **Shri Surendra Pal Singh:**
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Yashpal Singh:
Shri Ram Ratan Gupta:
Shri Rameshwar Tantia:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of Works, Housing and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether Government has taken any final decision to clear the Capital of all squatters; and

2189 (A) LSD—2.

(b) if so, what arrangements will be made by Government to rehabilitate the squatters?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation (Shri Jagannatha Rao): (a) Yes.

(b) Those who had squatted on Government and Public lands in Delhi|New Delhi prior to the special census taken in June|July, 1960 and whose names are included in that census are proposed to be provided alternative accommodation at selected sites.

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये लोग जो अनधिकृत रूप से सरकारी जमीनों पर बैठे हुए हैं और जिनको सरकार दूसरी जगहों पर बसाने जा रही है, क्या इनके जीविका उपार्जन पर असर पड़ेगा ?

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : दिल्ली में इस समय ५० हजार स्क्वाटर हैं । सन् १९५६-६० में हमने इनकी सेंसस ली थी । उस वक्त से भी ये बराबर बढ़ते जा रहे हैं । अगर तमाम दिल्ली को स्लम बना देना है तब तो इन को हर जगह रहने की इजाजत दी जा सकती है वरना नहीं । हम इनको जहाँ ले जाकर बसाना चाहते हैं वे साफ सुथरी जगहें होंगी और हम यह भी कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके ये अपने काम के नजदीक रह सकें ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप इनको दूसरी जगह हटा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि इनको इन जगहों पर जितनी आमदनी होती है उतनी ही दूसरी जगहों पर भी होगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : दिल्ली में बहुत काम है । इसकी तरफ से हम को कोई चिन्ता नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : यह झुग्गी झोपड़ी वालों का मसला बड़े समय से विचाराधीन है,

क्या में जान सकता हूँ कि यह कब तक हल हो जाएगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह मसला तो हल हो गया। गवर्नमेंट की पालिसी का एलान दो तीन दिन में होने वाला है। और हम इस काम को माननीय सदस्यों की मदद से पूरा कर लेंगे। हम यह नहीं इजाजत दे सकते कि तमाम आदमी आज नाजायज तरीके से जमीनों पर कब्जा कर लें और स्क्वेटर बन जाएँ और बाद में गवर्नमेंट से ८०-८० गज जमीन ले लें।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी मन्त्री जी ने कहा कि इनको साफ सुथरी जगहों पर बसाया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जिन जगहों पर सरकार इनको ले जाना चाहती है वहाँ पर इनके लिये एकोमोडेशन की क्या व्यवस्था है। क्या सरकार इनके लिये कोई एकोमोडेशन बनवाने जा रही है, उस पर कितना रुपया खर्चा होगा और वह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जमीनों तो हमने दिल्ली में बहुत एक्वायर कीं। अब हमारा पैरीफिरी पर जाने का इरादा है हम पांच छे कैम्प बनाना चाहते हैं और हम समझते हैं कि एक साल डेढ़ साल में माननीय सदस्यों की सहायता से इस मसले को हल कर लेंगे।

Shri Narendra Singh Mahida: When will the squatters be given quarters?

अध्यक्ष महोदय : बहुत जल्दी।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : यह देखने में आया है कि जो लोग समूह होते हैं वे तो अधिकारियों से मिल कर अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए राष्ट्र को विशेष परिस्थितियों के अन्दर कुछ ध्यान रखा जाये ताकि वह ठीक तरह बस सकें।

श्री मेहर चन्द खन्ना : गरीबों के लिए ही तो स्कीम है।

Mr. Speaker: Suggestion for action.

Shrimati Savitri Nigam: May I know how much land and other facilities will be provided to these squatters who have been registered in 1960-61?

Shri Mehr Chand Khanna: The idea is this. We are not going to place any premium on squatting by giving free lands to any squatter. That is the basic thing that we propose to do. We want to give sites and we want to develop them. Where we are going to have camps, the size of the plot is going to be smaller. We are going to provide water, lighting and all these arrangements. But we cannot accept this policy and principle that anyone who comes and squats in Delhi should get away with free land, etc. In that way, nothing will be left in Delhi.

Pochampad Project

+
*338 { **Dr. K. L. Rao:**
Shri Y. D. Singh:
Shri P. Venkatasubbaiah:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 658 on the 28th August, 1962 and state:

(a) whether the Central Water and Power Commission and its advisory committee have received the modified report of the Pochampad Multi-purpose Project; and

(b) if so, the decision taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) The question is under correspondence with the Government of Andhra Pradesh.

(b) Does not arise.

Dr. K. L. Rao: May I know whether the water requirement for this project can be met solely from the untied and free catchment of the river and therefore the sanction of this useful project, which is already greatly delayed, would be expedited?

Shri Alagesan: From the latest report it appears that there will be